

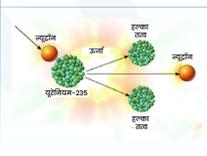
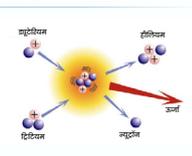
ब्याज टुडे

चीन ने गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक विस्फोट किया

पारंपरिक परमाणु और हाइड्रोजन बमों से भिन्न, 2 किलोग्राम का यह बम 1,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच गया। यह भविष्य के हथियारों के विकास और उपयोग में एक बड़ा कदम साबित होगा।

गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषताएं

- रासायनिक अभिक्रिया: यह परमाणु सामग्री के बिना शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है।
- दूसरी ओर, हाइड्रोजन बम मुख्य रूप से परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है।
- मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग: हाइड्रोजन बम में ईंधन के रूप में रेडियोधर्मी हाइड्रोजन समस्थानिकों (जैसे- ड्यूटेरियम या ट्रिटियम) का उपयोग किया जाता है। इस गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम में मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया गया है।
- मैग्नीशियम हाइड्राइड एक चांदी जैसा पाउडर होता है, जो ठोस अवस्था में हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल के रूप में कार्य करता है।
- प्रज्वलित होने पर इसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है, जो तेजी से हवा के साथ मिल जाती है और विस्फोटक सीमा तक पहुंचने पर गैस प्रज्वलित हो जाती है। इससे एक स्वतःस्फूर्त दहन चक्र (Self-sustaining combustion cycle) निर्मित होता है।
- विनाश का पैमाना: यह ट्राइनाइट्रो टॉलुईन (TNT) के विस्फोट बल का केवल 40% ही उत्पन्न करता है, लेकिन प्लूमीनियम मिश्रधातु जैसी सामग्रियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पादन के साथ अधिक थर्मल डैमेज रेडियस प्रदर्शित करता है।
- थर्मल डैमेज रेडियस: यह विस्फोट के बिंदु के केंद्र से वह दूरी है, जिसके भीतर ऊष्मा के कारण एक निश्चित स्तर का नुकसान होता है।
- इसके लिए न्यूनतम प्रज्वलन ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसमें विकिरण उत्पन्न किए बिना तीव्र व निरंतर ऊष्मा उत्पादित करने की क्षमता होती है।

परमाणु बम बनाम हाइड्रोजन बम		
पैरामीटर	परमाणु बम	हाइड्रोजन बम (थर्मोन्यूक्लियर बम)
अभिक्रिया का प्रकार	नाभिकीय विखंडन	नाभिकीय संलयन
प्रक्रिया	इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजित होता है। इसे बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन या तो स्वतः या न्यूट्रॉन के उपयोग के माध्यम से होता है।	इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। परमाणु बमों से भी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
प्रयोग किया जाने वाला ईंधन	यूरेनियम-235, प्लूटोनियम-239	ड्यूटेरियम व ट्रिटियम (हाइड्रोजन के समस्थानिक)
अभिक्रिया		

भारत में पहली बार 24 कैंरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई

कीमतों में उछाल लाने वाले प्रमुख वैश्विक कारक

- भू-राजनीतिक तनाव: सोने को निवेश के दृष्टिकोण से एक सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है। बढ़ते वैश्विक संघर्षों और आर्थिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सोने में निवेश की ओर आकर्षित किया है।
- यू.एस. फेडरल रिजर्व दर में कटौती: ब्याज दरें गिरने से सोने में निवेश का आकर्षण बढ़ जाता है। नकदी या बॉन्ड रखने की अवसर लागत कम होने पर सोना अधिक आकर्षक हो जाता है, क्योंकि सोना एक नॉन यील्डिंग एसेट है अर्थात यह एक ऐसी संपत्ति है, जिस पर ब्याज नहीं मिलता।
- अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना: डॉलर में गिरावट के कारण, सोने की कीमत अन्य मुद्राओं के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसका अर्थ है कि अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे सोने की मांग में वृद्धि होती है।
- केंद्रीय बैंक संचय: विशेष रूप से एशिया में, केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए आक्रामक तरीके से सोना खरीद रहे हैं।

भारत का स्वर्ण बाजार

- चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 2024 में भारत की सोने की मांग 802.8 टन तक पहुंच गई थी।
- भारत में लगभग 85% सोना आयात किया जाता है। इससे घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं।

भारत में सोने की उच्च मांग के लिए जिम्मेदार कारक

- वित्तीय सुरक्षा: सोने को विशेष रूप से मुद्रास्फीति या बाजार की अस्थिरता के दौरान मूल्य के दीर्घकालिक भंडार के रूप में विश्वसनीय माना जाता है।
- सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व: भारतीय संस्कृति में सोने को शुभ माना जाता है तथा दिवाली, धनतेरस एवं अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर भारतीय लोगों द्वारा उत्साहपूर्वक इसे खरीदा जाता है।
- शादियों के दौरान सोने की खरीदारी में तेजी: शादियों के दौरान सोने की खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि दुल्हन के लिए आभूषण एक पारंपरिक और प्रतिष्ठित उपहार होता है।
- तरल परिसंपत्ति: ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों के पास बैंक/ शेयर बाजार तक पहुंच नहीं होती है। उनके लिए सोना बचत, निवेश या यहां तक कि उधार लेने के लिए एक भरोसेमंद और तरल परिसंपत्ति के रूप में काम आता है।

स्वर्ण भंडार

भारत

- स्वर्ण अयस्क: स्वर्ण अयस्क (प्राथमिक) के मामले में सबसे बड़े संसाधन बिहार (43%) में स्थित हैं। उसके बाद राजस्थान (24.92%) और कर्नाटक (20%) का स्थान है।
- धातु सामग्री: धातु सामग्री के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार का स्थान है।

विश्व

- स्वर्ण भंडार के प्रमुख धारक: पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद जर्मनी और इटली का स्थान आता है।
- प्रमुख निर्यातक: विश्व एकीकृत व्यापार समाधान, 2023 के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी के बाद यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड का स्थान है।

जम्मू और कश्मीर के पहलगांम में आतंकी हमला हुआ

'मिनी-स्विट्जरलैंड' के रूप में प्रसिद्ध पहलगांम के सुंदर 'बैसरन घाटी' में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई नागरिकों की मौत हो गई।

इस हमले की जिम्मेदारी गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत सूचीबद्ध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक

राज्य प्रायोजित आतंकवाद: पाकिस्तान पर जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह, लॉजिस्टिक्स सहायता, प्रशिक्षण आदि प्रदान करने का आरोप लगाया गया है।

छिद्रिल (Porous) सीमाएं: नियंत्रण रेखा पर दुर्गम भूभाग होने की वजह से आतंकवादियों और हथियारों की घुसपैठ का पता लगाना और रोकना मुश्किल हो जाता है।

धार्मिक और नृजातीय तनाव: आतंकी समूह हिन्दू, मुस्लिम तथा अलग-अलग जनजातीय समूहों के सांप्रदायिक मिश्रण का सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए उपयोग करते हैं।

ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs): ये धन के प्रबंधन, भर्ती, प्रचार आदि के माध्यम से आतंकवाद को बनाए रखने में सहायता करते हैं।

OGWs ऐसे व्यक्ति/ समूह होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिए बिना आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स सहायता, खुफिया जानकारी जैसी गैर-लड़ाकू सहायता प्रदान करते हैं।

आगे की राह

सीमा सुरक्षा को मजबूत करना: मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में शामिल हैं- सुरक्षाबलों की सामरिक तैनाती, सीमा अवसंरचना को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि

राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करना: स्थानीय शासन और जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

सामुदायिक भागीदारी: नागरिक-सैन्य सहयोग (जैसे ग्राम रक्षा गार्ड); कट्टरपंथ विरोधी और पुनर्वास जैसे विश्वास निर्माण उपाय लागू करने की आवश्यकता है।

जम्मू-कश्मीर में भारत के आतंकवाद-रोधी उपाय

समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली: इसका उद्देश्य BSF की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि वो अवैध घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोक सके।

ऑपरेशन ऑल-आउट (2017): यह ऑपरेशन 2017 में शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के शीर्ष आतंकियों को निशाना बनाना है।

गांव की ओर वापसी: इसका उद्देश्य जनता का विश्वास जीतना और अलगाव को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर अभिशासन को बढ़ावा देना है।

कौशल विकास: इसके लिए सरकार हिमायत और उड़ान जैसी योजनाएं चला रही है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 'ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025' का मसौदा अधिसूचित किया

ये नियम चार ऊर्जा-गहन क्षेत्रों (एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली, और लुगदी एवं पेपर) के लिए GEI लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इससे उत्सर्जन में कटौती सुनिश्चित होगी।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) को आउटपुट या उत्पाद के संबंध में tCO₂e या इसके बराबर अन्य ग्रीनहाउस गैस के आधार पर मापा जाता है।

मुख्य नियमों पर एक नजर

GEI लक्ष्यों की गणना: इनकी गणना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी। अनुसूची में सूचीबद्ध प्रत्येक बाध्य संस्थाओं के लिए GEI लक्ष्य उनकी आधारभूत GEI के संबंध में अनुसूची के स्तंभ पांच के अनुसार होंगे।

बाध्य संस्थाओं के लिए अनुपालन संबंधी अनिवार्यताएं: इन्हे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 (बॉक्स देखें) के अनुसार वार्षिक रूप से GEI लक्ष्यों को पूरा करना होगा।

लक्ष्य को हासिल करने में आई कमी को पूरा करने के लिए भारतीय कार्बन बाजार (ICM) से कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र भी खरीदे जा सकते हैं।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति: यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा मुआवजा आरोपित किया जाएगा। यह मुआवजा अनुपालन वर्ष में कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र की औसत कीमत का दो गुना होगा और 90 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

कानूनी आधार: गैर-अनुपालन या नियमों का उल्लंघन करने संबंधी मामलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत देखा जाएगा।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 के बारे में

उत्पत्ति: इसे भारत में एक सुनियोजित कार्बन बाजार बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2023 में अधिसूचित किया गया है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (CCS) के व्यापार को सक्षम करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, दालना या समाप्त करना है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत तंत्र

अनुपालन तंत्र: यह उन बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो GHG उत्सर्जन तीव्रता में कमी संबंधी निर्धारित मानदंडों का पालन करके CCSs अर्जित करती हैं।

ऑफसेट तंत्र: यह उन गैर-बाध्य संस्थाओं के लिए है, जो ऐसी परियोजनाओं को पंजीकृत करवा सकती हैं, जो उत्सर्जन में कमी या उसे समाप्त कर सकती हैं तथा जिनके बदले में वे CCCs अर्जित कर सकती हैं।

नियमों का महत्त्व



राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) को प्राप्त करना: 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना



पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप: यह देशों को कार्बन बाजार के माध्यम से स्वेच्छा से सहयोग करने के साधन और तंत्र प्रदान करता है, ताकि वे अपने NDCs को पूरा कर सकें।



संधारणीय और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना: पारंपरिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों में।

इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग पूरी की

इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग तकनीक को भारतीय डॉकिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है।

अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक तब जरूरी होती है, जब सामान्य मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट्स लॉन्च करने की आवश्यकता होती है।

स्पेडेक्स मिशन के बारे में

यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। इसमें PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित दो लघु उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन शामिल है। डॉकिंग का अर्थ है अंतरिक्ष में तीव्र गति से यात्रा कर रहे दो उपग्रहों को आपस में जोड़ना।

प्राथमिक उद्देश्य: अंतरिक्ष में दो लघु उपग्रहों SDX01 (चेजर) और SDX02 (टारगेट) की डॉकिंग; स्वतः संचालित तरीके से दूसरे उपग्रह (टारगेट) के पास आना एवं उससे सटीकता के साथ जुड़ जाना; तथा अनडॉकिंग क्षमताओं को विकसित और प्रदर्शित करना है।

स्पेडेक्स अंतरिक्ष यान को यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर (URSC), बेंगलुरु द्वारा इसरो के अन्य केंद्रों (VSSC, LPSC, SAC, IISU, और LEOS) के सहयोग से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है।

URSC, बेंगलुरु को पहले ISRO सैटेलाइट सेंटर (ISAC) के नाम से जाना जाता था। यह उपग्रहों के निर्माण और संबंधित उपग्रह प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रमुख केंद्र है।

मिशन का महत्त्व

रणनीतिक अंतरिक्ष क्षमता: ऑर्बिटल डॉकिंग तकनीक भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ानों, सैटेलाइट मरम्मत मिशनों, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी है।

राष्ट्रीय उपलब्धि: इस मिशन के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन गया, जिसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग में सफलता अर्जित की है। इससे पहले यह उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ने हासिल की है।

भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को सक्षम बनाना: यह मिशन भविष्य के मिशनों जैसे चंद्रयान-4 में मदद करेगा, विशेष रूप से तब जब पृथ्वी से GNSS सहायता न मिल रही हो।

IMF ने "वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO): ए क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट" रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में व्यापार के संबंध में तनाव और नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति के चलते वैश्विक संवृद्धि दर पूर्वानुमान को जनवरी 2025 के अपडेट से घटाकर 2.8% कर दिया गया है। इसे भारत के लिए 6.2% अनुमानित किया गया है। साथ ही, श्रम बल में वृद्ध हो रहे लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वस्थ एजिंग (आयुवृद्धि) सुनिश्चित करने के पक्ष में नीतियां बनाने की सिफारिश भी की गई है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र वृद्धि: घटती जन्म दर और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण देश अपने जनसांख्यिकीय के महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहे हैं। इसके तहत डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ट्रैग की ओर संक्रमण हो रहा है।

दुनिया की जनसंख्या की औसत आयु 2020 से लेकर इस सदी के अंत तक 11 साल बढ़ने का अनुमान है।

स्वस्थ एजिंग: दीर्घायु में वृद्धि के साथ-साथ, वृद्ध हो रहे लोगों की कार्यात्मक क्षमता में भी समय के साथ सुधार हुआ है।

वर्ष 2022 में 70 साल के व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता वर्ष 2000 में 53 साल के व्यक्ति के समान थी।

स्वस्थ एजिंग के लाभ

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि: स्वस्थ एजिंग से 2025-50 तक वैश्विक औसत सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% की वृद्धि होने का अनुमान है।

इसमें भारत का योगदान सबसे अधिक होगा, क्योंकि 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों की हिस्सेदारी 2025-50 की अवधि में तेजी से बढ़ेगी।

श्रम बल भागीदारी पर प्रभाव: लक्षित स्वास्थ्य नीतियां वृद्ध श्रमिकों को अपनी श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं।

स्वस्थ एजिंग सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें

समग्र दृष्टिकोण: सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए पेंशन संबंधी सुधार, प्रशिक्षण, कार्यस्थल को अनुकूल बनाना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने वाले हस्तक्षेपों को लागू किया जाना चाहिए।

श्रम बल भागीदारी अंतराल को कम करना: जनसांख्यिकीय संबंधी बाधाओं से निपटने के लिए बेहतर कार्य-जीवन संतुलन, किफायती बाल देखभाल सुविधा आदि के माध्यम से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

अन्य सुर्खियां

तंबाकू

सरकार ने 'तंबाकू बोर्ड नियम, 1976' में संशोधन किया। अब वर्जीनिया तंबाकू उगाने वाले किसानों के पंजीकरण की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है।

तंबाकू के बारे में

माना जाता है कि तंबाकू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से हुई थी। दुनिया भर में तंबाकू की 60 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं।

तंबाकू की खेती के लिए आदर्श दशाएं:

तापमान: 20°-27°C के बीच;

वर्षा: न्यूनतम 500 मिमी; 1200 मिमी से अधिक वर्षा नुकसानदायक;

मृदा: रेतीली या रेतीली दोमट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त;

अवधि: 90 से 120 दिनों की पाला-मुक्त अवधि।

भारत में उत्पादन

स्थिति: चीन के बाद भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अविनिर्मित तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

प्रमुख राज्य: मुख्य रूप से गुजरात (उत्पादन का 30%), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसकी खेती की जाती है।

स्थायी जमा सुविधा (SDF)

भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन फ्रेमवर्क के रूप में स्थायी जमा सुविधा (SDF) को शुरू हुए तीन वर्ष हुए।

SDF के बारे में

SDF वस्तुतः तरलता प्रबंधन का एक साधन है। इसकी सहायता से अब RBI बिना किसी जमानत या संपार्श्विक/ सरकारी प्रतिभूतियों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) से तरलता को अवशोषित करता है। इसलिए, RBI प्रतिभूतियों को दिए बिना बैंकों से अधिशेष तरलता को कम कर सकता है।

मुख्य विशेषताएं:

SDF ने फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (FRRR) की जगह ली है। ज्ञातव्य है कि FRRR वस्तुतः तरलता समायोजन सुविधा (LAF) कॉरिडोर की न्यूनतम दर है।

यह क्षणिक प्रकृति की तरलता को अवशोषित करेगा, क्योंकि इसे ओवरनाइट के आधार पर संचालित किया जाएगा, लेकिन RBI चाहे तो इसकी अवधि को बढ़ा भी सकता है।

LAF के लिए पाल सभी बैंक और संस्थाएं इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

SDF, ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक अवकाश और सप्ताहांत सहित सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगा।



ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ)

सुप्रीम कोर्ट ने नीरी/ NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) को ताजमहल के आप-पास मौजूद कांच उद्योग के ताजमहल पर प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है।

➤ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समय-समय पर TTZ के लिए आदेश जारी किए थे (उदाहरण के लिए, TTZ के अंतर्गत उद्योगों में कोयला/ कोक पर प्रतिबंध, 1996)।

ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के बारे में

- अवस्थिति: ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल स्मारक के चारों ओर (ट्रेपीजॉयड या समलम्ब चतुर्भुज) लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित क्षेत्र है। इस अधिसूचित क्षेत्र का उद्देश्य प्रदूषण से ताजमहल को बेरंग होने से बचाना है।
- कवरेज: इस जोन में यूनेस्को की सूची में शामिल तीन विश्व धरोहर स्मारक (ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी) शामिल हैं।
- केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ताज ट्रेपेजियम जोन (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया है।
- क्षेत्रों की श्रेणियां: TTZ में क्षेत्रों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट जोन में श्रेणीबद्ध किया गया है।



अरुण-3 जल विद्युत परियोजना

भारत-नेपाल ने अरुण-3 जलविद्युत परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों की शुरुआत की।

अरुण-3 जल विद्युत परियोजना के बारे में

- अवस्थिति: अरुण नदी (कोसी की सहायक नदी) पर पूर्वी नेपाल के संखुवासभा जिले में।
- विशेषताएं: यह 900 मेगावाट की रन-ऑफ-रिवर परियोजना है।
- परिचालन: SJVN अरुण-III पावर डेवलपमेंट कंपनी (SAPDC) इसे पांच वर्ष की निर्माण अवधि सहित 30 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर आधार पर विकसित कर रही है।
- SAPDC भारत की सतलुज जलविद्युत निगम (SJVN) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो SJVN और नेपाल सरकार के बीच महत्वपूर्ण सहयोग को दर्शाती है।



आधार

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ई-नाम/ e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और किसान समूहों हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया।

➤ आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 में भारत की संचित निधि पर भारत किसी भी सब्सिडी, लाभ या सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है।

आधार के बारे में

- विशेषताएं: यह 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है, जो पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह नागरिकता या मूल निवास का प्रमाण नहीं है। इसमें बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय दोनों प्रकार की जानकारी होती है।
- जारीकर्ता: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)।
- पालता: सभी आयु वर्ग के भारत के निवासी।



डेविस स्ट्रेट प्रोटो-माइक्रोकॉन्टिनेंट

वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपे एक महाद्वीप की खोज की है। इसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो-माइक्रोकॉन्टिनेंट नाम दिया गया है।

➤ प्रोटो-माइक्रोकॉन्टिनेंट "अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थलमंडल के क्षेत्र होते हैं, जो पतले महाद्वीपीय स्थलमंडल के क्षेत्र द्वारा प्रमुख महाद्वीपों से पृथक होते हैं।"

डेविस स्ट्रेट प्रोटो-माइक्रोकॉन्टिनेंट के बारे में

- यह डेविस जलडमरूमध्य के नीचे स्थित नया खोजा गया जलमय माइक्रोकॉन्टिनेंट का खंड है।
- डेविस जलडमरूमध्य लैब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि यह भूभाग प्राचीन टेक्टोनिक बदलावों के दौरान आंशिक रूप से अलग हो गया था, लेकिन यह आस-पास के महाद्वीपों से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया।
- इसके परिणामस्वरूप, यह तलछट की परत और पानी के नीचे समुद्र के भीतर जलमय रहा।



मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल

एक नई रेडियोकार्बन स्टडी में, मेहरगढ़ की कृषि बस्तियों की समयावधि 8000 ईसा पूर्व की जगह 5200 ईसा पूर्व बताई गई है। इस स्टडी में एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) डेटिंग का उपयोग किया गया है।

मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल के बारे में

- यह एक नवपाषाण स्थल है, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है।
- इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता से पहले लगभग 3000 साल तक निरंतर मानव बसावट के साक्ष्य मिले हैं।
- स्थल की प्रमुख विशेषताएं:
 - प्रारंभिक कृषि बस्ती: यहां से गेहूं और जौ तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं।
 - यहां से कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
 - मेहरगढ़ से मिट्टी की ईंटों से बनी संरचनाओं, शवाधान गृह, मृदाभांड (जिन्हें तोगाऊ कहा जाता है) आदि के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं।



गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC)

पिंजौर (हरियाणा) स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC) से 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड गिद्धों को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया।

गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र (VCBC), पिंजौर के बारे में

- उत्पत्ति: इसे वर्ष 2001 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के 'डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्प्रीशीज़' फंड द्वारा स्थापित किया गया था।
- साझेदार: इसे हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BHNS) ने संयुक्त रूप से तैयार किया है।
- लक्ष्य: गिद्धों की तीन प्रजातियों (सफेद पुट्टे वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्ध) को बचाना।
- अवस्थिति: वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा।
- उपलब्धि: इसके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि डाईक्लोफेनाक (एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा) गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण थी।

सुर्खियों में रहे स्थल



सऊदी अरब (राजधानी: रियाद)

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता की।

भौगोलिक अवस्थिति:

- यह मध्य पूर्व में अवस्थित है। यहां पूर्ण राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है।
- यह अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार अरब प्रायद्वीप के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4/5वें भाग पर है।
- भूमि सीमाएं: इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यमन से लगती हैं।
- समुद्री सीमाएं: फारस की खाड़ी, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी से लगती हैं।
- यहां इस्लाम के दो सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं।

भौगोलिक विशेषताएं

- यह दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा देश है, जहां कोई नदी नहीं है।
- जलवायु: कठोर व शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिससे तापमान अत्यधिक रहता है।
- प्राकृतिक संसाधन: तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क आदि

